



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2003/माघ 15, 1924

No. 111]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2003/MAGHA 15, 1924

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2003

199

का. आ. 133(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29)

की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन माथेरन और उसके आस-पास के प्रदेश को पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के रूप में अधिसूचित करते हुए और उद्योगों, संक्रियाओं, प्रक्रियाओं और क्षेत्र में ऐसे अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों पर जिनका पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, निर्बन्धन अधिरोपित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की संख्या का0आ0 167 (अ) तारीख 6 फरवरी, 2002 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गयी थी जिसमें उक्त प्रारूप अधिसूचित के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 6 फरवरी, 2002 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केंद्रीय सरकार ने सभी प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार किया है,

अतः अब केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप धारा (2) के खण्ड (v) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य के माथेरन और उसके आस-पास के प्रदेश को, माथेरन पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल' कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है।

2. उक्त पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के अंतर्गत 214.73 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र और 200 मीटर का बफर जॉन आता है और इसमें माथेरन नगर परिषद् और इसके आस-पास का क्षेत्र शामिल होगा। पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल का मानचित्र उपाबंध-क में है। ग्रामों की सूची के साथ-साथ सीमा का वर्णन उपाबंध-ख में है और 200 मीटर के बफर जॉन में अपवाद और छूटें उपाबंध-ग में हैं।

3. वन में (नगर पालिका क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों) सभी क्रियाकलाप भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे। संरक्षित क्षेत्रों में सभी क्रियाकलाप वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

4. पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में निम्नलिखित क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे:

(क) पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के लिए आंचलिक मास्टर प्लान:-

(i) पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के लिए आंचलिक मास्टर प्लान इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, 1966 (1966 का महाराष्ट्र अधिनियम XXXVII) के अधीन तत्सभाव विहित प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा और भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। आंचलिक मास्टर प्लान को सभी संबंधित विभागों को सम्यक रूप से शामिल करके तैयार किया जाएगा। जिससे इसमें पर्यावरणीय बातें समाहित की जा सकें। आंचलिक मास्टर प्लान में वन-विरहित क्षेत्रों के प्रत्यावर्तन, जलागम क्षेत्रों का प्रबंध, वाटरशेड प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और नमी संरक्षण, ईंधन लकड़ी के लिए व्यवस्था, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताएं और पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे कोई अन्य पहलू जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता हो।

(ii) अंचल के लिए मास्टर प्लान सभी विद्यमान गोथान, गोथान विस्तार क्षेत्रों, वनों, हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, फलोद्यानो, जनजातीय क्षेत्रों जिसके अन्तर्गत जनजातीय ग्रामक भी है, प्राकृतिक झरनों, प्राकृतिक विरासत स्थलों, ऐतिहासिक नेरल माथेरन रेल लाइन और अन्य पर्यावरणिकी और पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों को सीमांकित करेगी। हरित उपयोगों जैसे फलोद्यानों उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों और अन्य ऐसे ही स्थानों से भूमि के उपयोग का कोई परिवर्तन पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के लिए मास्टर प्लान में केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना गैर हरित उपयोगों और जनजातीय उपयोगों का गैर जनजातीय उपयोगों के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। अंचल के लिए मास्टर प्लान में यातायात को, विशेषकर पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में जाने वाले यातायात को विनियमित करने के लिए उपाय भी इंगित किए जाएंगे और अनुबंधित अधिकथित किए जाएंगे।

(iii) माथेरन नगर पालिका क्षेत्र के भीतर और बाहर क्षेत्रों में पृथक उप अंचल मास्टर प्लान होंगे जो अंचल के लिए मास्टर प्लान के घटक के रूप में राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जाएंगे

और ऐसे उप अंचल मास्टर प्लानों के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय की सहमति अभिप्राप्त की जाएगी । 5000 से अधिक जनसंख्या वाले पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में सभी निवासियों के लिए भी क्षेत्र विकास प्लान होने चाहिए । उप अंचल मास्टर प्लान में गोथान और गोथान विस्तार क्षेत्रों के लिए विकास संबंधी विनियम भी शामिल होंगे ।

(iv) पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के लिए आंचलिक मास्टर प्लान और उप आंचलिक मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन लंबित रहने तक माथेरन नगर पालिका सीमाओं में अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात, अनुज्ञेय ऊंचाई, मंजिलों की अधिकतम संख्या और भू सीमा क्षेत्र के विद्यमान प्राचलों में कोई वृद्धि नहीं होगी । माथेरन नगर पालिका सीमाओं में स्टिल्ट्स, मेजेनाइन और बेसमेंट अनुज्ञात नहीं की जाएगी । माथेरन नगर पालिका क्षेत्र में नए सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे किंतु; मरम्मत और प्रत्यावर्तन संबंधी कार्यों को अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु इनमें अवसंरचना संबंधी परिवर्तन अंतर्वलित नहीं होगा और यह माथेरन नगर पालिका सीमाओं के विद्यमान प्राधिकृत कुरसी क्षेत्र पर ही होंगे । माथेरन नगर पालिका क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में -

- (1) जनजातीय क्षेत्र/वन अंचल/हरित अंचलों और कृषि क्षेत्रों में कोई कमी नहीं होगी ।
- (2) भवनों की आंत्यतिक ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होगी और मंजिलों की संख्या भूतल धन एक ऊपर की मंजिल से अधिक नहीं होगी ।
- (3) उपाबंध- घ में उल्लिखित क्रियाकलाप राज्य और स्थानीय विधियों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए मानीटरी समिति द्वारा अनुज्ञात किए जा सकेंगे ।
- (4) सभी विकास क्रियाकलापों जिनके अंतर्गत भवनों का परिवर्धन, परिवर्तन, भंजित करना, मरम्मत, नवीकरण और प्रत्यावर्तन भी है, के लिए मानीटरी समिति का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा और विरासत मंजूरी यदि आवश्यक हो, के अध्यक्षीन होंगे ।
- (5) मानीटरी समिति, यदि आवश्यक हो तो, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त उपाय विहित करेगी ।

(ख) औद्योगिक इकाईयां : - इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से या उसके पश्चात् केवल अप्रदूषित, अपरिसकंटमय लघु उद्योग और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित उद्योग जो पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में देशी माल से उत्पाद उत्पादित करते हो और जिनसे पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ता हो, को ही अनुज्ञात किया जाएगा । तदनुसार महाराष्ट्र सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे और इन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा । ऐसे कोई मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं होंगे जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित 27 जनवरी, 1994 की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना संख्यांक का0आ0 60 (अ) के उपबंधों के विरुद्ध हों ।

(ग) **खदान क्रिया और खनन:-** खदान क्रिया और खनन क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में प्रतिबंधित होंगे। पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में कोई नया खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाएगा तथापि, निगरानी समिति माथेरन नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में स्थानीय निवासीय गृह निर्माण के सन्निर्माण और परंपरागत सड़क बनाने और अनुरक्षण संक्रम के लिए स्थल मूल्यांकन के आधार पर अपेक्षित सामग्रियों की सीमित खदान क्रिया के लिए विशेष अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकारी होगी। कोई खदान क्रिया सीधी पहाड़ी ढलान या अधिक कटाव वाले क्षेत्रों पर या वन भूमि पर नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना में "सीधी पहाड़ी ढलान" से ऐसा पहाड़ी ढलान अभिप्रेत है, जो 20 डिग्री या इससे अधिक के प्रवण का है।

(घ) **वृक्ष:-** वन, सरकारी, राजस्व या निजी भूमि में, वन भूमि की दशा में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना और सरकारी, राजस्व और निजी भूमि की दशा में संबंधित जिला कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा के बिना जो उस प्रक्रिया के अनुसार, जो राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमित की जाएगी, कोई वृक्ष नहीं गिराया जाएगा।

(ड.) **पर्यटन:-** (1) पर्यटन क्रियाकलाप, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के परामर्श से और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा विशेषकर पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास पर बल देते हुए तैयार की जाने वाली पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार होंगे। पर्यटन मास्टर प्लान आंचलिक मास्टर प्लान का एक घटक रूप भी होगी। जब तक कि पर्यटन मास्टर प्लान पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी जाती, तब तक माथेरन नगर पालिका परिषद् क्षेत्र के भीतर नई और अतिरिक्त पर्यटन सुविधाएं जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स, सराय, लॉजिंग और बोर्डिंग हाऊस आदि पर पाबंदी होगी। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यटन मास्टर प्लान का अनुमोदन लंबित रहने तक माथेरन नगर पालिका परिषद् क्षेत्र के भीतर विद्यमान विरासत भवनों का विरासत होटलों के रूप में उपयोग करने की अनुज्ञा विरासत संरक्षण समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के मानीटरी समिति द्वारा ही दी जाएगी।

(2) पर्यटन मास्टर प्लान पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के चलाये जाने की क्षमता के विस्तृत अध्ययन पर आधारित होगी जो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर अनुमोदन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप, पर्यटन के लिए विकास विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की अनुज्ञा केवल इस पर्यटन प्लान या चलाए जाने की क्षमता के अध्ययन के प्राचल के भीतर ही दी जाएगी। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यटन मास्टर प्लान के अनुमोदित किए जाने तक पर्यटन क्रियाकलाप और पर्यटन के लिए विकासों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को माथेरन नगर पालिका के क्षेत्र से बाहर पर्यावरण

और वन मंत्रालय द्वारा अधिकथित मार्गदर्शनों के अध्यक्षीय मानीटरी समिति द्वारा विस्तृत विश्लेषण किए जाने और अनुमोदित किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(च) **प्राकृतिक विरासत:-** पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में मूल्यवान प्राकृतिक विरासत के स्थल की पहचान विशिष्ट रूप से, चट्टान निर्माणों, जल प्रपातों, पूलों, झरनों, तंगघाटियों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, सैरो, सवारियों इत्यादि के रूप में की जाएंगी और प्लानों को उनके प्राकृतिक स्थापन में उनके संरक्षण को आंचलिक मास्टर प्लान और उप आंचलिक मास्टर प्लान में समाविष्ट किया जाएगा । इन स्थलों पर या उनके निकट सन्निर्माण क्रियाकलापों को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा कठोर मार्गदर्शन तैयार किए जाएंगे जिसके अंतर्गत पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था भी है । विरासत स्थलों पर या इनके आस-पास विकास या निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को राज्य सरकार के कानूनी उपबंधों जो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1955 में तैयार किए गए तथा समय-समय पर यथा संशोधित प्राकृतिक और मानव निर्मित विरासत स्थलों के संरक्षण के माडल विनियमों के अनुसार बनाए गए थे, के अन्तर्गत विनियमित किए जाएंगे । राज्य सरकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर उनके संरक्षण या परिरक्षण के लिए उचित प्लान तैयार करेगी । ये प्लान आंचलिक मास्टर प्लान और उप आंचलिक मास्टर प्लान के भाग रूप होंगे ।

(छ) **मानव निर्मित विरासत:-** ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के भवनों, संरचनाओं, आर्टिफेक्टों, क्षेत्रों और प्रसीमाओं की पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण, विशिष्टतया उनके बाहरी स्वरूप (और जहां उचित समझा जाए, वहां आंतरिक स्वरूप) के संरक्षण की योजना तैयार की जाएगी और उसे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा । राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में, विशेष रूप से माथेरन नगर पालिका क्षेत्र में भवन और अन्य क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी, जिससे कि शहरों का और पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल का विशेष स्वरूप और सुभिन्न परिवेश बना रखा जा सके ।

विरासत स्थलों पर या इनके आसपास विकास या सन्निर्माण संबंधी क्रिया कलापों को राज्य सरकार के उन कानूनी उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1995 में प्राकृतिक और मानव निर्मित विरासत स्थलों के अनुसार बनाए गए थे और समय-समय पर संशोधित किए गए ।

(ज) **भूगर्भ जल:-** प्लाट के स्वामी का सदभावी कृषि और घरेलू उपभोग के लिए भूगर्भ जल का निष्कर्षण अनुज्ञात है । औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय काम्प्लेक्स के लिए भूगर्भ जल के निष्कर्षण के लिए राज्य भूगर्भ जल बोर्ड से, जितनी मात्रा में निष्कर्षण किया जाना है सहित, लिखित अनुज्ञात अपेक्षित होगी । भूगर्भ जल के विक्रय की इस अधिसूचना के पैराग्राफ 4

के अन्तर्गत गठित मानीटरी समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। कृषि क्रियाकलापों सहित संदूषण अथवा जल प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।

(अ) **प्लास्टिक का उपयोग:-** कोई भी व्यक्ति माथेरन म्युनिसीपल काउंसिल क्षेत्र के भीतर प्लास्टिक के थैलों का उपयोग नहीं करेगा। पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के भीतर प्लास्टिक, लेमीनेट्स और टैट्रा पैक के उपयोग को मानीटरी समिति द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(ख) **पहाड़ी ढलान का संरक्षण:-** (i) अंचल मास्टर प्लान पहाड़ी ढलानों पर ऐसे क्षेत्रों को उपदर्शित करेगी। (ii) विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलान या अत्यधिक कटाव वाले ढलानों पर किसी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ग) **बहिस्रावों का निष्सारण:-** पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के भीतर किसी अनुपचारित बहिस्राव का निष्सारण प्रतिषिद्ध है। किसी बहिस्राव को चाहे वह उपचारित हो अथवा अनुपचारित, पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल के भीतर किसी जलाशय अथवा जल स्रोत में निष्सारण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(घ) **ठोस अपशिष्ट:-** (i) स्थानीय प्राधिकारी ठोस अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नकरणीय घटकों में पृथक् करने की योजना बनाएंगे।

(ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री अधिमानतः कंपोस्टिंग या कृमि पालन द्वारा पुनः चक्रित की जा सकेगी; अकार्बनिक सामग्री पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य अवस्थानों पर व्यव्यनित की जा सकेगी।

(iii) ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना में 'ठोस अपशिष्ट' में घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक और उद्यान संबंधी अपशिष्ट भी होंगे।

(ड) **प्राकृतिक झरने:-** (i) सभी प्राकृतिक झरनों के जल आगम क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए प्लान और जो सूख गए हैं उनके प्राकृतिक संस्थापन में उनके पुनर्नवीकरण को अंचल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा।

(ii) इन क्षेत्रों में या उनके निकट विकास क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा कठोर मार्गदर्शन तैयार किए जाएंगे।

(ढ) **यातायात:-** कोई यानीय यातायात सिवाय एंबुलेंस और फायर इंजन और ठोस अपशिष्ट परिवहन के लिए ट्रैक्टर को माथेरन नगर पालिका सीमाओं के भीतर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

5.(1) निगरानी समिति : - केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक समिति का गठन करती है, जिसे मानीटरी समिति कहा जाएगा जो इस अधिसूचना के उपबंधों की मानीटरी और अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(2) मानीटरी समिति में दस स अनअधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(3) मानीटरी समिति में पर्यावरण और वन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार, शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार में से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि होगा जिसे पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के बारे में विशेषज्ञ ज्ञान हो और पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन के कम से कम दो प्रतिनिधि और जिलाधिकारी, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र राज्य और कोई अन्य व्यक्ति जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नामोदित किया जाएगा, इसके सदस्य होंगे।

(4) मानीटरी समिति का अध्यक्ष कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति होगा जिसे प्रबंधकीय अथवा प्रशासनिक कार्य का अनुभव हो और जो स्थानीय समस्याओं को समझता हो।

(5) जिलाधिकारी, जिला रायगढ़ मानीटरी समिति का संयोजक होगा।

6. (1) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य:- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियां प्रयोग करते हुए, मानीटरी समिति को ऐसे कृत्यों का विशेष रूप से जिनको अधिसूचना में प्रगणित किया गया है निर्वहन करने और उनकी आनुषंगिक सभी बातों को करने के लिए (उन कृत्यों के सिवाय, जो समय-समय पर यथा संशोधित 27 जनवरी, 1994 की पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा निष्पादित किए जाने अपेक्षित हैं) सशक्त करता है।

(2) मानीटरी समिति का यह कर्तव्य होगा कि यदि उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध का होना उसके ध्यान में आता है और इसके द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न किए जाने की दशा में वह वन (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करेगा।

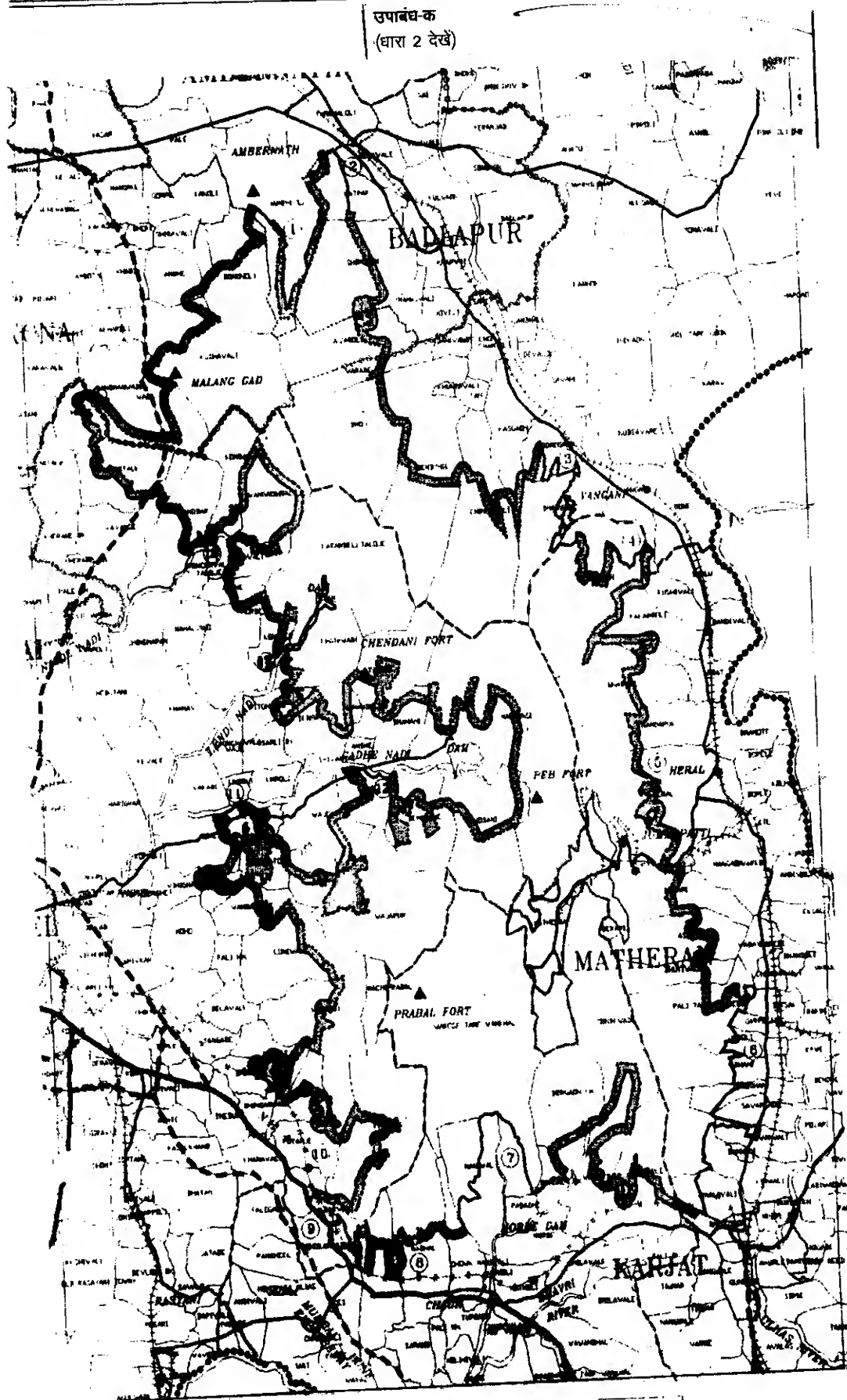
(3) मानीटरी समिति अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत मानीटरी समिति का कोई सदस्य पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत शिकायत दर्ज करेगा।

7. **अपील:-** (1) कोई व्यक्ति मानीटरी समिति के विनिश्चय अथवा आदेश से व्यथित होता है तो वह ऐसे विनिश्चय अथवा आदेश के विरुद्ध, भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय को अपील करेगा ।
- (2) इस पैराग्राफ के अधीन की गई प्रत्येक अपील ज्ञापन में मामले के तथ्यों का संक्षिप्त कथन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उस विनिश्चय अथवा आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है और विनिश्चय अथवा आदेश द्वारा व्यथित होने और चाहे गये उपचार के कारणों के बारे में सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित किया जाना चाहिए ।
- (3) अपील का प्रत्येक ज्ञापन प्रभावित व्यक्ति द्वारा निर्णय अथवा आदेश प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर किया जाना चाहिए ।
- (4) पर्यावरण और वन मंत्रालय अपील के पक्षकारों को अपने मामले को प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात अपील ज्ञापन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा ।

[फा. सं. जे-20011/1/99-आई. ए.-III]

डा. वी. राजागोपालन, संयुक्त सचिव

उपाबंध-क
(धारा 2 देखें)



प्रस्तावित पारि-संवेदनशील क्षेत्र
मध्यवर्ती क्षेत्र
(पारि-सं. क्षेत्र के आस-पास 200 मीटर)

उपाबंध (ख)

(धारा 2 देखें)

माथेरन पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की सीमा

पारि-संवेदनशील अंचल की सीमा, जिसमें माथेरन पहाड़ी स्टेशन नगर परिषद का क्षेत्र, एम एम आर के लिए प्रादेशिक योजना का संलग्न वन क्षेत्र और वन क्षेत्र के आसपास का मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, निम्नवत पारिभाषित होगा।

दिशा	सीमाएं
उत्तर	जाम्भीवली गांव से होकर जानेवाली वन क्षेत्र की सीमा, फिर जाम्भीवली, चिखालाली गांवों से होकर गुजरने वाली मध्यवर्ती क्षेत्र की बाहरी सीमा फिर उल्हास नगर तहसील के चिखालोली गांव से होकर गुजरने वाली वन क्षेत्र की सीमा
पूर्व	कतरप गांव से होकर गुजरने वाली वन क्षेत्र की सीमा, फिर शिरगांव सवरोली वरदे, भोज, बेनारील चिनवेली, कांसगांव गोरेगांव से होकर गुजरने वाले मध्यवर्ती क्षेत्र की बाहरी सीमा, फिर गोरेगांव, उल्हासनगर तहसील के धवले और कजरात तहसील के बेदिसागांव, गांवों से होकर गुजरने वाली वन क्षेत्र की सीमा फिर बेदिसागांव गांवों से होकर गुजरने वाली मध्यवर्ती क्षेत्र और वन क्षेत्र की बाहरी सीमा, फिर खुशीवाली कालानबोली, दामत, भादावल, मामदापुर, नेराल, मनगांव टर्फ वारेदी भीकारे असई भूटीवाली, पाली टर्फ वरदे गांवों से होकर गुजरने वाले वफर क्षेत्र की बाहरी सीमा, फिर पाली टर्फ वरदे, उमरोली, असने, कसाने, वनजाले, कारीवाली, पाली वाली, कारजत तहसील के भीसेगांव से होकर गुजरने वाली वन क्षेत्र की सीमा
दक्षिण	कारजत तहसील के गांव भीसेगांव से होकर गुजरने वाली मध्यवर्ती क्षेत्र की बाहरी सीमा, फिर वारले, बाद विहार सोनदेवाड़ी, वोरेगांव के एच बोरेगांव बीके गांव से होकर गुजरने वाली एक क्षेत्र की बाहरी सीमा, फिर खालापूर तहसील के चौक मनीवाली नदहाल लोदीवली से हाकर गुजरने वाली मध्यवर्ती की बाहरी सीमा फिर बोरेगांव वी के बार रोस टर्फ वनखल, नानीवाल मध्यवर्ती सीमा
पश्चिम	भोकारपादा, बारवई गांवों से होकर गुजरने वाली वन क्षेत्र की सीमा फिर बारवई पाली बीके पोयांजे मोहपे भिनगरवाडा, भेरले, वारडोली, लोनीवाली, वानगानी टर्फ वाजे एमवीवाली, विहाईघर, नेरे गांव से हाकर गुजरने वाली मध्यवर्ती क्षेत्र की

	बाहरी सीमा, फिर गांव नेरे से होकर गुजरने वाली वन क्षेत्र की सीमा फिर संगारटोली, चेरावली वाजापुर वाजे गडहे गांव से होकर गुजरने वाली मध्यवर्ती क्षेत्र की बाहरी सीमा फिर गांव गडहे से होकर गुजरने वाली वन क्षेत्र की सीमा, फिर पनवेल तहसील के गांव देहरंग, धोदानी, मालदुगे, धामानी तायसई, खैरवाड़ी, करमावेली धुनद्रे, उसराली बीके, रीतघर, खैरवाड़ी कोन्डले, मोरने, अम्बे, टर्फतलोजे, शिरियावली, कारमबेली टर्फ तलओजे, वारंगी टर्फ तलोजे कोनडप, मोहोदर वावानजे, निताले, क्रोम से होकर गुजरने वाली वफर क्षेत्र की बाहरी सीमा, फिर उल्लासनगर तहसील के वाड़ी, बंधनवाड़ी खुसावली, अभ्मी, शीरावली, बोहोनले, जम्भावली गांवों से होकर गुजरने वाली टर्फ क्षेत्र की बाहरी सीमा
--	---

उपर्युक्त सीमाबद्ध क्षेत्र के भीतर माथेरन पहाड़ी स्टेशन का संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र, करजत तहसील की परिषद और पानेवल तहसील में माची प्रभाल मालडुंगे का संपूर्ण गांव परिस्थितिकी संवेदनशील अंचल में सम्मिलित है

टिप्पणी

- (i) पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल के भीतर मध्यवर्ती क्षेत्र में मुम्बई महानगर क्षेत्र 1996-2011 के लिए स्वीकृत प्रादेशिक योजना में केवल हरित अंचल 1 और हरित अंचल 2 शामिल होंगे और 14 आपवादिक मामलों में पारिस्थितिकी संवेदी अंचल वन क्षेत्र तक निर्बंधित ।
- (ii) माथेरन नगरपरिषद के नगरकरणीय अंचल 1 के सिवाय नगरकरणीय अंचल 1, नगरकरणीय अंचल 2 और औद्योगिक क्षेत्र का कोई पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल में नहीं आता।

माथेरन पारि-संवेदी क्षेत्र की सूची

जिला: रायगढ़

तहसील-कारजात

क्र०सं०	ग्राम	प्रास्थिति
1	असई	भागतः
2	अशाणे	भागतः
3	बेदिसगांव	भागतः
4	वेकारे	भागतः
5	भदवाल	भागतः
6	भुसेगांव	भागतः
7	भूटीवाली	भागतः
8	दमसत	भागतः
9	हलीवाली	भागतः

क्र०सं०	ग्राम	प्रास्थिति
10	कलामबोली	भागतः
11	किरवाली	भागतः
12	कोशाणे	भागतः
13	कुशीवाली	भागतः
14	माम्दपुर	भागतः
15	मनगांव टर्फ वरेड़ी	भागतः
16	माथेरन	पूर्ण
17	नेरल	भागतः
18	पाली टर्फ वरेड़ी	भागतः
19	उमरोली	भागतः
20	वंजले	भागतः

टिप्पण:- समूचा माथेरन का संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र सम्मिलित किया गया है।

तहसील: खालापुर

क्र०सं०	ग्राम	प्रास्थिति
21	बोरगांव वीके	भागतः
22	बोरगांव के एच	भागतः
23	चौक मनीवाली	भागतः
24	लोधीवली	भागतः
25	नाधल	भागतः
26	नानीवाली	भागतः
27	सोंदेवाडी	भागतः
28	वाड विहार	भागतः
29	वारोस टर्फ वंखल	भागतः
30	वावर्ले	भागतः

तहसील पेनवेल

क्रम.संख्या	ग्राम	प्रास्थिति
31.	अंबे टर्फ तलोजे	भागतः
32.	अम्बेवाली	भागतः
33.	बारवाई	भागतः
34.	बोर्ले	भागतः
35.	भिनगार	भागतः
36.	भोकरपाड़ा	भागतः
37.	चेरावली	भागतः
38.	क्रोम	भागतः
39.	देहारंग	भागतः
40.	धमानी	भागतः
41.	धोदानी	भागतः
42.	दुंद्रे	भागतः
43.	गाधे	भागतः
44.	कारावेली	भागतः
45.	कम्बे टर्फ तलोजे	भागतः
46.	खैरवाड़ी	भागतः
47.	कोंडाले	भागतः
48.	कोण्डप	भागतः
49.	लुनीवाली	आंशिक
50.	माचीप्राबल	पूर्ण
51.	महोदर	भागतः
52.	मालडुंगे	भागतः
53.	मोहोपे	भागतः
54.	मोर्बे	भागतः
55.	नेरे	भागतः
56.	निताले	भागतः
57.	पाली वीके	भागतः
58.	पोयन्जे	भागतः
59.	रितगढ़	भागतः
60.	संगाटोली	भागतः
61.	श्रीवली	भागतः
62.	तामसाई	भागतः
63.	उसरली वी के	भागतः
64.	वावन्जे	भागतः

65.	विहिघर	भागतः
66.	वाजपुर	पूर्ण
67.	वाजे	भागतः
68.	वागांनी टर्फ तलोजे	भागतः
69.	वागांनी टर्फ वाजे	भागतः
70.	वारडाली	भागतः

जिला: थाणे

तहसील उल्हासनगर

क्रम. संख्या	ग्राम	प्रास्थिति
71.	अंभे	भागतः
72.	वन्धनवाडी	भागतः
73.	बंदशील	भागतः
74.	भोज	भागतः
75.	वोहोनोली	भागतः
76.	चिखलोली	भागतः
77.	चिंचवाली	भागतः
78.	दहावाले	भागतः
79.	गोरेगाँव	भागतः
80.	जाम्भीवाली	भागतः
81.	कासगाँव	भागतः
82.	कटरूप	भागतः
83.	कुशावली	भागतः
84.	सखरोली	भागतः
85.	शिरावली	भागतः
86.	शिरगाँव	भागतः
87.	वंगानी	भागतः
88.	वराडे	भागतः
89.	वाडी	भागतः

उपाबंध-ग

(धारा 2 देखें)

ई एस जेड की सीमा में उपांतरण -- 200 मी. मध्यवर्ती अंचल में अपवाद और छूट

मानचित्र 1 और 2 के साथ तत्संबंधी निर्देश संख्या	क्षेत्र या गांव जिसके लिए छूट चाही गई है	भूमि उपयोग	टिप्पणियां
जिला थाणे			
1	जाम्भीवली (अम्बरनाथ)	नगरकरणीय अंचल - 1	अम्बरनाथ नगर परिषद का यू- 1 अंचल, एफ अंचल से मध्यवर्ती क्षेत्र 200 मी. से कम है या कोई मध्यवर्ती क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है।
2	जाम्भावली (अम्बरनाथ) कत्रप, (बादलापुर)	औद्योगिक क्षेत्र और नगरकरणीय अंचल 1	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा योजनाकृत अम्बरनाथ अतिरिक्त औद्योगिक सम्पदा अंचल- I और कुलगांव बादलापुर नगर परिषद के यू- I अंचल, एफ अंचल से सटा है, मध्यवर्ती क्षेत्र 200 मी० से कम है और कोई मध्यवर्ती क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है।
जिला रायगढ़			
3.	गोरेगांव, वनगानी	नगरकरणीय अंचल- 2	एफ अंचल से सटा स्वीकृत प्रादेशिक योजना का यू- 2 अंचल
4.	वनगानी	नगरकरणीय अंचल 1	वन अंचल से सटा 1973 में स्वीकृत योजना में नियोजित डारमिटरी नगर के यू- 1 अंचल
5.	नेराल	नगरकरणीय अंचल- 1	एफ अंचल से संलग्न 1999 की स्वीकृत प्रादेशिक योजना का यू- 1 अंचल
6.	पाली टर्फ वरदे उमरोली, असाने, कसाने, वनजाले कारीवाली पालीवाली भीसेगांव	नगरकरणीय अंचल-2	एफ अंचल से संलग्न स्वीकृत प्रादेशिक योजना का यू- 2 अंचल
7.	वोरेगांव बीके., वारोस टर्फ वनखल, नानीवल	मोरबे डेम	नवी मुम्बई और अन्य संलग्न शहरों को फायदा देने के लिए पेयजल आपूर्ति के लिए मिट्टी का बांध निर्माणाधीन है। बांध के फर्श का उत्खनन भूमि की स्थानीय सामग्री को उपयोग करके तटबंध को मजबूत बनाने खुदाई और मरम्मत और

			रख-रखाव आवश्यक हो सकता है
8.	चौक मनिवाली नदहाल, लोदी वाली	रेल लाइन	मध्यवर्ती क्षेत्र, रेल लाइन तक निर्बंधित है जो कि विकास के लिए वास्तविक मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।
9.	वारवई, पाली बीके.	सड़क और रेल लाइन	मध्यवर्ती क्षेत्र, रेल लाइन तक निर्बंधित है जो कि विकास के लिए वास्तविक मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।
10.	भिंजरवाड़ा, भेरले	रेल लाइन	मध्यवर्ती क्षेत्र, रेल लाइन तक निर्बंधित है जो कि विकास के लिए वास्तविक मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।
11.	नेरे, सनगारटोली	गड़हे नदी	नदी, प्राकृतिक मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में कार्य करती है इसलिए कोई अतिरिक्त मध्यवर्ती क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है।
12.	गड़हे	गड़हे नदी	नदी, प्राकृतिक मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में कार्य करती है इसलिए कोई अतिरिक्त मध्यवर्ती क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है।
13.	खैरवाड़ी	लन्देह नदी	नदी, प्राकृतिक मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में कार्य करती है इसलिए कोई अतिरिक्त मध्यवर्ती क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है।
14.	मोहोदर	नन्दे नदी	नदी, प्राकृतिक मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में कार्य करती है इसलिए कोई अतिरिक्त मध्यवर्ती क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है।

उपाबंध-घ

(धारा 4(क)(iv)(3) देखें)

माथेरन पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल में अनुज्ञेय विकासोन्मुख क्रियाकलाप**1. वन अंचल**

1.1 जब कोई भूमि उच्चतम न्यायालय के तारीख 12 दिसम्बर, 1996 के आदेश के अनुसार यथापरिभाषित आरक्षित वन, संरक्षित वन, अधिगृहित वन के बाहर स्थित है ऐसी भूमि का विकास को हरित क्षेत्र- 2 के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

2. हरित अंचल-2

2.1 हरित अंचल-2 (जी-2अंचल) में अनुज्ञेय उपयोग निम्नानुसार है:-

(क) किसी कृषि भूमि के, जिसे कृषि संबंधी कार्यकलापों के अनन्य प्रयोजन के लिए धारित किया गया है, राजस्व विभाग अभिलेख के अनुसार धारक के वास्तविक उपयोग के लिए आवासीय इकाईयों के लिए।

(ख) उद्यान कृषि, पुष्पकृषि और कृषि और चावल के सहबद्ध क्रियाकलाप, और इससे संबंधित कार्य और पोहा मिल, कुक्कुट फार्म, पशुशाला, सूकरालय और भेड़ फार्म ।

(ग) धार्मिक स्थान श्मशान और कब्रिस्तान ।

(घ) विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केन्द्र ।

(ड.) क्लिनिक और औषधालय

(च) सड़क और पुल, रेल, भूमिगत पाइपलाइन और केबल, विद्युत पारेषण लाइन, संचार टावर, वाटरशेड प्रबंधन के लिए लघु रोक बांध, रोपवे ।

2.2 प्लॉट का आकार कम से कम 0.4 हैक्टेयर होगा ।

3. हरित अंचल -1

3.1 हरित अंचल -1(जी-1 अंचल) में अनुज्ञेय उपयोग निम्नानुसार है:-

(क) किसी कृषि भूमि के, जिसे कृषि संबंधी कार्यकलापों के अनन्य प्रयोजन के लिए धारित किया गया है, राजस्व विभाग अभिलेखों के अनुसार धारक के वास्तविक उपयोग के लिए आवासीय इकाईयों के लिए।

(ख) हॉलिडे रिसोर्ट और हॉलिडे होम

(ग) 2.5 हैक्टेयर से अन्धून के प्लॉट पर कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों और दुकानों के साथ-साथ शैक्षणिक, चिकित्सीय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाएं

- (घ) विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केन्द्र
- (ङ.) क्लिनिक, औषधालय और स्वास्थ्य केन्द्र
- (च) एल पी जी सिलिडरों का भंडारण
- (छ) उद्यानकृषि, पुष्पकृषि, और कृषि और चावल की सहबद्ध क्रियाकलाप और पोहा मिल, कुक्कुट फार्म, पशुशाला सुकरालय और भेड़ फार्म ।
- (ज) धार्मिक स्थान, श्मशान और कब्रिस्तान ।
- (झ) उद्यान, बाग, खेल का मैदान, जन सुविधाओं के साथ शिविर मैदान
- (ट) सड़क और पुल, रेल, भूमिगत पाइपलाइन और केबल, विद्युत पारेषण लाईन, संचार टावर, वाटरशेड प्रबंधन के लिए लघु रोक बांध।

3.2 प्लाट का आकार कम से कम 0.4 हैक्टेयर होगा ।

4. नगरीकरणीय अंचल -2 में अनुज्ञेय क्रियाकलाप निम्नानुसार है

- (क) किसी कृषि भूमि के, जिसे कृषि संबंधी क्रियाकलापों के अनन्य प्रयोजन के लिए धारित किया गया है, राजस्व विभाग अभिलेखों के अनुसार धारक के वास्तविक उपयोग के लिए आवासीय इकाईयों के लिए।
- (ख) अप्रदूषणकारी वैज्ञानिक संस्थाएं
- (ग) विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केन्द्र
- (घ) क्लिनिक, औषधालय और स्वास्थ्य केन्द्र
- (ङ.) निगरानी समिति के पूर्व अनुमोदन से होटल, पर्यटक रिसोर्ट, हॉलिडे होम, मोटल और क्लब हाउस
- (च) केवल आवासीय प्रयोजनों के लिए मकान
- (छ) उद्यान, बाग, खेल का मैदान और जन सुविधाओं के साथ शिविर मैदान।
- (ज) धार्मिक स्थान, श्मशान और कब्रिस्तान ।
- (झ) उद्यान कृषि, पुष्पकृषि और कृषि और चावल सहबद्ध क्रियाकलाप पोहा मिल, कुक्कुट पालन फार्म, पशुशाला, सुकरालय और भेड़ फार्म ।
- (ट) फुटकर दुकान, थोक दुकान, रेस्टोरेंट और बैंक
- (ठ) सरकारी कार्यालय
- (ढ) गैरेज, पेट्रोल पम्प, आटोमोबाइल मरम्मत कार्य
- (ण) निगरानी समिति के पूर्व अनुमोदन से लोक सेवाएं और जल उपचार संयंत्र, मलजल उपचार संयंत्र, ठोस अपशिष्ट उपचार और व्ययन सुविधाएं, विद्युत उपस्टेशन, गैस संकर्म, फायर ब्रिगेड, पुलिस स्टेशन, टेलीफोन एक्सेचेंज, बस शेल्टर, टर्मिनल और डिपो के उपयोगिता स्थापना
- (फ) सड़क और पुल, रेल, भूमिगत पाइपलाइन और केबल, विद्युत पारेषण लाइन, संचार टावर, वाटरशेड प्रबंधन के लिए लघु रोक बांध

4.2 पैरा 4.1 के मद (ख) से (च) तक के लिए प्लॉट का न्यूनतम आकार 2,000 वर्ग मी० होगा।

5. नगरीयकरण अंचल -1

5.1 माथेरन नगर परिषद् क्षेत्र के लिए उपक्षेत्रीय मास्टर योजना को तैयार करने में माथेरन शीर्षक रिपोर्ट मुम्बई महानगर प्रदेश विरासत संरक्षण सोसाइटी द्वारा आरंभ किए गए व्यापक सूचीबद्ध प्रस्ताव की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

5.2 अंतिम प्रादेशिक योजना 1973 के भाग के रूप में तैयार किए गए अभिन्यास के अधीन क्षेत्र से बाहर आनेवाले नेराल और वांगनी के नगरकरणीय अंचल- 1 के भीतर की भूमि का विकास हरित अंचल 1 के लिए उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

6. गौथान और गौथान विस्तार

6.1 अंचलों पर विचार किए बिना निम्नलिखित उपबंध गौथान और गौथान विस्तार को विनियमित करेंगे।

6.2 प्रादेशिक योजना के प्रवृत्त होने पर गौथान की सीमाएं वे होंगी जो राजस्व मानचित्र में दर्शायी गई है।

6.3 गौथान विस्तार को निगरानी समिति द्वारा केवल वर्तमान गौथान निवासियों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के आधार पर अनुज्ञा की जा सकेगी।

6.4 गौथान और गौथान विस्तार में भूमि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए किया जा सकेगा:

(क) आवासीय।

(ख) दुकान, गैरेज, लघु भोजनालय, बैंक और डाकघर।

(ग) विद्यालय।

(घ) सामुदायिक केन्द्र और अन्य सामाजिक संस्थाएं।

(ङ) धार्मिक स्थान।

(च) क्लिनिक, औषधालय और स्वास्थ्य केन्द्र।

(छ) आवश्यक लोक सेवाएं और उपयोगिताएं जिसके अन्तर्गत स्थानीय सरकारी कार्यालय भी हैं।

(ज) प्रत्येक प्लॉट पर 5 पशुओं की सीमा के अध्यधीन पालतु पशुओं के लिए पशुशाला

(झ) परम्परागत घरेलू उद्योग।

() फसल, चारा, खाद, कृषि उपस्कर और अन्य वैसी ही आवश्यकताओं का भंडारण।

(ट) उद्यान, बाग और खेल का मैदान।

(ठ) जन सुविधाएं।

(ड) घरेलू और वाणिज्यिक उपयोगों के लिए ईंधन का भंडारण।

6.5 फर्श क्षेत्र अनुपात और आच्छादित तल

क्षेत्र	फर्श क्षेत्र अनुपात	आच्छादित तल
गौथान	1.00	----
गौथान विस्तार	0.40	40 प्रतिशत

टिप्पण: उपर उल्लिखित अंचलों का वर्गीकरण मुम्बई महानगर प्रदेश सितम्बर 1999 की स्वीकृत प्रादेशिक योजना के अनुसार है।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi. the 4th February, 2003

S. O. 133(E).—Whereas a draft notification under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), inviting objections or suggestions against the proposal for notifying Matheran and surrounding region as an Eco-sensitive Zone and imposing restriction on industries, operations, processes and other developmental activities in the region which have detrimental effect on the environment was published in the Gazette of India *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. No. 167(E) dated the 6th February, 2002;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 6th day of February, 2002;

And whereas all objections and suggestions received have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies Matheran and surrounding region in the State of Maharashtra as the Matheran Eco-sensitive Zone (herein after called "the Eco-sensitive Zone").

2. The said Eco-sensitive Zone covers an area of 214.73 sq. kms. and a 200 mts. buffer zone and it shall consist of the area of the Matheran Municipal Council and its environs. The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A. A description of the boundary along with the list of villages is at Annexure-B and the exceptions and exemptions in the 200 mts. buffer zone are at Annexure-C.

3. All activities in the forest (both within and outside municipal areas) shall be governed by the provisions of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) and Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980). All activities in the protected areas shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

4. The following activities shall be regulated in the Eco-sensitive Zone namely:

(a) Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone:—

- (i) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government by following a procedure similar to that prescribed under the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act XXXVII of 1966), within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and approved by the Ministry of Environment and Forests in the Government of India. The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned Departments for integrating environmental considerations into it. The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, provision for fuel wood, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (ii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing gaothans, gaothan expansion areas, forests, green areas, horticultural areas, agricultural areas, orchards, tribal areas including tribal hamlets, natural springs, natural heritage sites, historic Neral-Matheran railway line and other environmentally and ecologically sensitive areas. No change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture, parks and other like places to non-green uses and tribal uses to non-tribal uses shall be permitted in the Zonal Master Plan without the prior approval of the Central Government in the Ministry of Environment and Forests. The Zonal Master Plan shall also indicate measures and lay down stipulations for regulating traffic, especially through traffic in the Eco-sensitive Zone.
- (iii) The areas within and outside Matheran Municipal Council area shall have separate Sub-zonal Master Plans which may be prepared by the State Government as a component of the Zonal Master Plan and concurrence of the Ministry of Environment and Forests shall be obtained on such Sub-zonal Master Plans. All habitations in the Eco-sensitive Zone having population of more than 5000 should also have Area Development Plans. The Sub-zonal Master Plan shall also include development regulations for gaothan and gaothan expansion areas.
- (iv) Pending the preparation of and approval by the Ministry of Environment and Forests to the Zonal Master Plan and Sub-zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone, there shall be no increase in the existing parameters of permissible Floor Area Ratio, permissible height, maximum number of storeys and ground coverage for buildings in Matheran Municipal limits. Stilts, Mezzanines and basements shall not be permitted in Matheran Municipal limits. No new constructions shall be allowed but repairs and restoration may be permitted provided that it does not involve structural

changes and are on the existing authorised plinth area in the Matheran Municipal limits. In areas other than Matheran Municipal limits:-

- (1) There shall be no reduction in Tribal Area, Forest Zone, Green Zones and Agricultural Area.
- (2) Absolute height of buildings shall not exceed 9 meters and the number of storeys shall not exceed ground plus one upper storey.
- (3) Activities mentioned in Annexure-D may be permitted by the Monitoring Committee subject to the State and local laws and the rules and regulations made there under.
- (4) All development activities including additions, alterations, demolitions, repairs, renovations and restorations of buildings shall require prior approval of the Monitoring Committee and shall be subject to heritage clearance if necessary.
- (5) The Monitoring Committee shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

(b) Industrial units:- On or after the publication of this notification in the Official Gazette, only non-polluting, non-hazardous small-scale and service industries, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industries producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone and which do not cause any adverse environmental impact shall be permitted. Accordingly, guidelines shall be drawn by the Government of Maharashtra and approved by the Ministry of Environment and Forests. No such guidelines shall conflict with the provisions of the Environment Impact Assessment Notification number S.O. 60(E) dated the 27th January, 1994 of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests and as amended from time to time.

(c) Quarrying and Mining:- Quarrying and Mining activities shall be banned in the Eco-sensitive Zone and no fresh mining lease shall be granted. However, the Monitoring Committee shall be the authority to grant special permission for limited quarrying of materials required for the construction of local residential housing and traditional road making and maintenance work in Matheran Municipal Council area based on site evaluation. No quarrying shall be permitted on steep hill slopes or areas with a high degree of erosion or on forestlands.

Explanation:- In this notification, "steep hill slope" means a hill slope with a gradient of 20 degrees or more.

(d) Trees:- There shall be no felling of trees whether on Forest, Government, Revenue or private lands, without the prior permission of the State Government in case of forest land, and the respective District Collector in case of Government, Revenue and private land, as per procedure which shall be laid down by the State Government.

(e) Tourism:- (1) Tourism activities shall be as per a Tourism Master Plan, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development, to be prepared by the Department of Tourism of the State Government in consultation with the Ministry of Tourism of Government of India and approved by the Ministry of Environment and Forests. The Tourism Master Plan shall also form a component of the Zonal Master Plan. There shall be a ban on new and additional tourist facilities like hotels, restaurants, inns, lodging and boarding houses and the like within Matheran Municipal Council area till the Tourism Master Plan is approved by the Ministry of Environment and Forests. Pending the approval of the Tourism Master Plan by the Ministry of Environment and Forests, the use of existing heritage buildings for heritage hotels within Matheran Municipal Council area may be permitted by the Monitoring Committee only after it is approved by the Heritage Conservation Committee.

(2) The Tourism Master Plan shall be based on a detailed Carrying Capacity Study of the Eco-sensitive Zone which may be carried out by the State Government and submitted to the Ministry of Environment and Forests for approval within a period of two years from the date of publication of this notification. All new tourism activities, developments for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted only within the parameters of the Tourism Master Plan and carrying capacity study. Till the Tourism Master Plan is approved by the Ministry of Environment and Forests, outside Matheran Municipal Council area, new tourism activities, development for tourism and expansion of existing tourism activities may be permitted only after a detailed analysis is carried out and approved by the Monitoring Committee subject to guidelines laid down by the Ministry of Environment and Forests.

(f) Natural Heritage:- The sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone shall be identified, particularly rock formations, waterfalls, pools, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides and the like and plans for their conservation in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and Sub-zonal Master Plan. Strict guidelines shall be drawn up by the State Government to discourage construction activities at or near these sites including under the garb of providing tourist facilities. Development or construction activities at or around the heritage sites shall be regulated under the statutory provisions of the State Government, made in accordance with the Model Regulations for Conservation of Natural and Man-made Heritage Sites formulated by the Ministry of Environment and Forests in 1995 and as amended from time to time. The State Government may draw up proper plans for their conservation or preservation within one year from the date of publication of this notification. These plans shall form a part of the Zonal Master Plan and Sub-zonal Master Plan.

(g) Man-made heritage:- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetical, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation, particularly their exteriors (and wherever deemed appropriate their interiors also) shall be prepared and incorporated in the Zonal and Sub-zonal Master Plan within one year from the date of publication of this notification. Guidelines shall be issued by

the State Government to regulate building and other activities in the Eco-sensitive Zone, particularly in Matheran Municipal Council area, so that the special character and distinct ambience of the town and the Eco-sensitive Zone are maintained. Development or construction activities at or around the heritage sites shall be regulated under the statutory provisions of the State Government, made in accordance with the Model Regulations for Conservation of Natural and Man-made Heritage Sites formulated by the Ministry of Environment and Forests in 1985 and as amended from time to time.

(h) Ground Water:- Extraction of ground water for the bona-fide agricultural and domestic consumption of the occupier of the plot is allowed. Extraction of ground water for industrial, commercial or residential complexes shall require prior written permission, including the amount that can be extracted, from the State Ground Water Board. No sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the Monitoring Committee constituted under paragraph 4 of this notification. All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water, including from agriculture activities.

(i) Use of plastics:- No person shall use plastic bags within Matheran Municipal Council area. The use of plastics, laminates and tetra-packs within the Eco-sensitive Zone shall be regulated by the Monitoring Committee.

(j) Protection of Hill Slopes:- (i) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where construction shall not be permitted.

(ii) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(k) Discharge of effluents:- (i) The discharge of any untreated effluent is prohibited within the Eco-Sensitive Zone.

(ii) No effluent, either treated or untreated, shall be permitted to be discharged into any water body or water source within the Eco-sensitive Zone.

(l) Solid Wastes:- (i) The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of at environmentally acceptable locations.

(iii) No burning or incineration of solid wastes shall be permitted.

Explanation:- In this notification, "solid wastes" shall include domestic, industrial, commercial and garden wastes.

(m) Natural Springs:- (i) The catchment area of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(ii) Strict guidelines shall be drawn up by the State Government to ban development activities at or near these areas.

(n) **Traffic:-** No vehicular traffic shall be permitted within the Matheran Municipal limits, except ambulance and fire engine and use of tractor for transportation of solid waste.

5. **Monitoring Committee:-**(1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Monitoring Committee, to monitor and ensure compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consists of not more than ten members.

(3) The Monitoring Committee shall consist of a representative each from the Ministry of Environment and Forests, Central Pollution Control Board, Department of Environment of the Government of Maharashtra, Department of Urban Development of the Government of Maharashtra, subject expert knowledgeable about the Eco-sensitive Zone and at least two representatives of non-government organisations working in the field of environment (including heritage conservation) and the Collector of Raigad District, in the State of Maharashtra and any other persons or persons nominated by the Central Government.

(4) The Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local problems.

(5) The Collector of Raigad District shall be the Convener of the Monitoring Committee.

6. **Powers and functions of the Monitoring Committee:-** (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 and read with Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby empowers the Monitoring Committee to discharge the functions specifically enumerated in the notification and to do all things incidental thereto (except the function as are required to be performed by the Central Government under the provisions of the Environment Impact Assessment Notification of 27th January, 1994, as amended from time to time).

(2) It shall be the duty of the Monitoring Committee to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 if commission of any offences under the said Act comes to its notice and in case of non-compliance of the directions issued by it.

(3) The Monitoring Committee or member of the Monitoring Committee authorised by it shall file complaints under the Environment (Protection) Act, 1986.

6. **Appeal:-** (1) Any person aggrieved by a decision or order of the Monitoring Committee shall prefer an appeal against such decision or order to the Government of India in the Ministry of Environment and Forests.

(2) Every memorandum of appeal under this paragraph shall precisely state the facts of the case, the particulars of the decision or order appealed against and the reasons for being aggrieved by the decision or order and the remedy sought for and shall be addressed to the Secretary to the Government of India, Ministry of Environment and Forests, New Delhi.

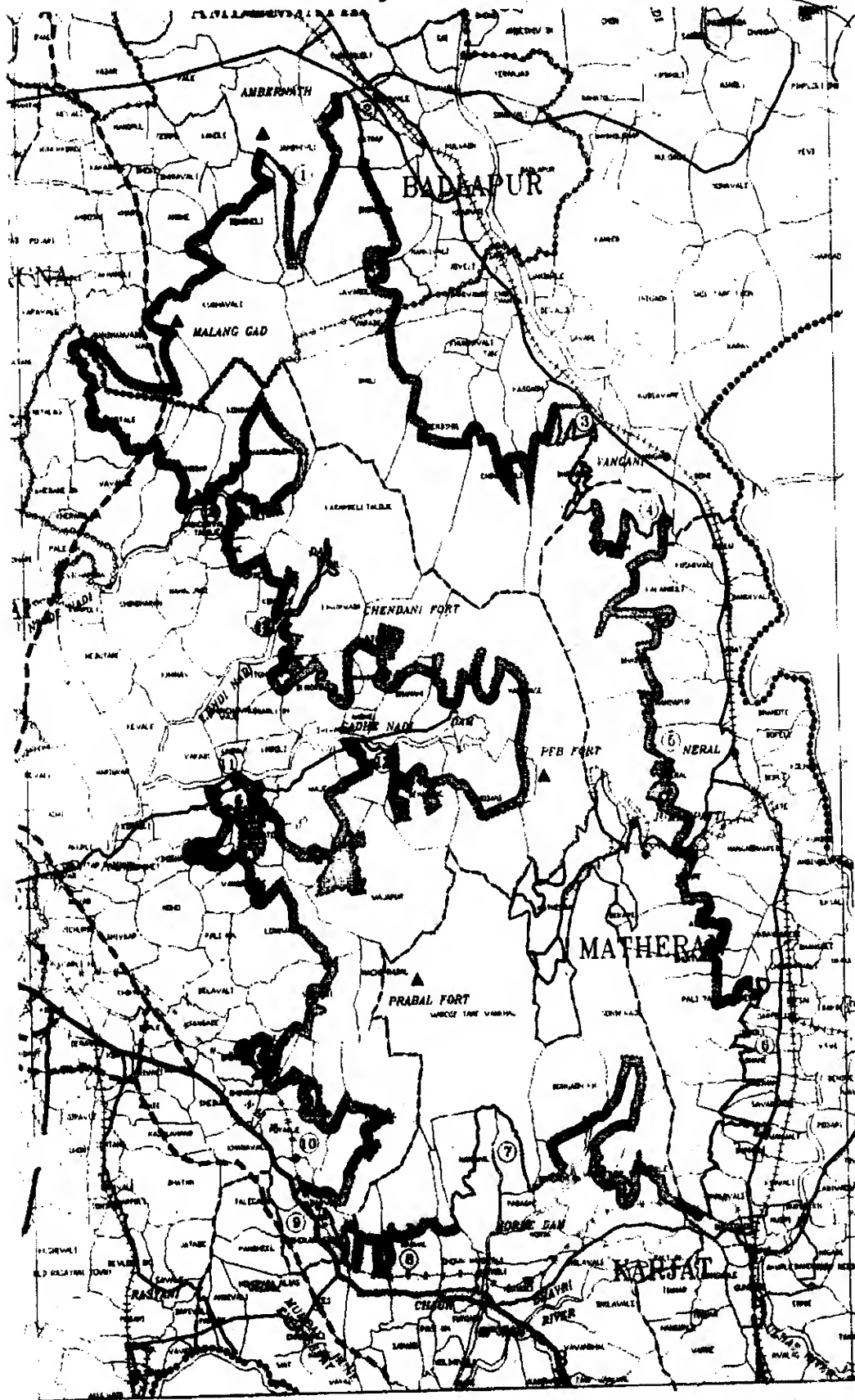
(3) Every memorandum of appeal shall be made within ninety days from the date of receipt of the decision or order by the affected person.

(4) The Ministry of Environment and Forests shall, after giving the parties to the appeal an opportunity to present their case, dispose of the appeal within ninety days of date of receipt of the memorandum of appeal.

[F. No. J-20011/1/99-I. A. -III]

Dr. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

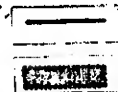
Annexure-A
(see section 2)



PROPOSED ECO-SENSITIVE ZONE

BUFFER ZONE
(200 M. AROUND ESZ)

8



Annexure-B

(see section 2)

BOUNDARY OF MATHERAN ECO-SENSITIVE ZONE

The boundary of the Eco-Sensitive Zone comprising area of Matheran Hill Station Municipal Council, contiguous Forest Zone of the Regional Plan for MMR and Buffer Zone around the Forest Zone shall be defined as follows:

Direction	Bounded By
North	Boundary of the Forest Zone passing through village Jambhivali, then outer boundary of the buffer zone passing through Village Jambhivali, Chikhaloli; then boundary of Forest Zone passing through village Chikhaloli of Ulhasnagar Tehsil.
East	Boundary of the Forest Zone passing through Village Katrap; then outer boundary of the buffer zone passing through villages Shirgaon, Savroli, Varde, Bhoj, Bensil, Chinvali, Kasgaon, Goregaon; then boundary of Forest Zone passing through villages Goregaon, Dagle of Ulhasnagar Tehsil and Bedisagaon of Karjat Tehsil; then outer boundary of buffer zone and Forest Zone passing through villages Bedisagaon; then outer boundary of buffer zone passing through villages Kushivali, Kalamboli, Damat, Bhadaval, Mamdapur, Neral, Mangaon Tarf Waredi, Bhikare, Asai, Bhutiwali, Pali Terf Varde; then boundary of Forest Zone passing through villages Pali Tarf Verde, Umroli, Asane, Kasane, Vanjale, Kariwali, Paliwali, Bhisegaon of Karjat Tehsil.
South	The outer boundary of buffer zone passing through village Bhisegaon of Karjat Tehsil then outer boundary of buffer zone passing through villages Warele, Wadvihar, Sondewadi, Boregaon Kh., Boregaon Bk.; then boundary of Forest Zone passing through villages Boregaon Bk., Warose Tarf Wankhal, Naniwal; then outer boundary of buffer zone passing through villages Chowk Maniwali, Nadhal, Lodhivali of Khalapur Tehsil.
West	Boundary of Forest Zone passing through villages Bhokarpada, Barwai, then outer boundary of buffer zone passing through Villages Barwai, Pali Bk., Poyanje, Mohope, Bhingarwada, Bherle, Wardoli, Loniwali, Wangani Tarf Waje, Ambivali, Vihighar, Nere; then boundary of Forest Zone Passing through village Nere; then outer boundary of buffer zone passing through villages Sangartoli, Cheravali, Wajapur, Waje, Gadhe; then boundary of Forest Zone passing through village Gadhe; then outer boundary of buffer zone passing through villages Dehrang, Dhodani, Maldunge, Dhamani, Tamsai, Khairwadi, Karambeli, Dhundre, Usarli Bk. Ritghar, Khairwadi, Kondale, Morbe, Ambhe Tarf Taloje, Shiriavali, Karambeli Tarf Taloje, Wangani Tarf Taloje, Kondap, Mohodar, Vavanje, Nitale, Chorme of Panvel Tehsil; then outer boundary of buffer zone passing through villages Wadi, Bandhanwadi, Khusavali, Ambhe, Shiravali, Bohonole, Jambhivali of Ulhasnagar Tehsil.

Within the above bounded zone, the entire Municipal Area of Matheran Hill Station Municipal Council in Karjat Tehsil and entire village of Machi Prabhal, Maldunge in Parvel tehsil is included in the Eco-Sensitive Zone.

Note:

- i. *The Buffer Zone within the Eco-Sensitive Zone shall encompass only Green Zone 1 and Green Zone 2 of the sanctioned Regional Plan for Mumbai Metropolitan Region 1996-2011 and in 14 exceptional cases the Eco-Sensitive Zone is restricted to Forest Zone.*
- ii. *No area of Urbanisable Zone 1, Urbanisable Zone 2 and Industrial Zone shall fall within the Eco-Sensitive Zone or the Buffer Zone except the Urbanisable Zone 1 of Matheran Municipal Council*

LIST OF VILLAGES OF MATHERAN ECO-SENSITIVE ZONE

DISTRICT : RAIGAD

TEHSIL : KARJAT

S No.	VILLAGE	STATUS
1.	Asai	Partial
2.	Ashane	Partial
3.	Bedisgaon	Partial
4.	Bekare	Partial
5.	Bhadwal	Partial
6.	Bhisegaon	Partial
7.	Bhutiwali	Partial
8.	Damat	Partial
9.	Halivali	Partial
10.	Kalamboli	Partial
11.	Kirwali	Partial
12.	Koshane	Partial
13.	Kushivali	Partial
14.	Mamdapur	Partial
15.	Mangaon Tarf Waredi	Partial
16.	Matheran	Full
17.	Neral	Partial
18.	Pali Tarf Waredi	Partial
19.	Umroli	Partial
20.	Wanjale	Partial

Note : The entire Matheran Municipal Council area is included.

TEHSIL : KHALAPUR

S No.	VILLAGE	STATUS
21.	Borgaon Bk.	Partial
22.	Borgaon Kh.	Partial
23.	Chowk Maniwali	Partial
24.	Lodhivali	Partial
25.	Nadhal	Partial
26.	Naniwali	Partial
27.	Sondewadi	Partial
28.	Wad Vihar	Partial
29.	Warose Tarf Wankhal	Partial
30.	Wawarle	Partial

TEHSIL : PANVEL

S No.	VILLAGE	STATUS
31.	Ambhe Tarf Taloje	Partial
32.	Ambivali	Partial
33.	Barwai	Partial
34.	Bherle	Partial
35.	Bhingar	Partial
36.	Bhokarpada	Partial
37.	Cheravali	Partial
38.	Chorme	Partial
39.	Deharang	Partial
40.	Dhamani	Partial
41.	Dhodani	Partial
42.	Dundre	Partial
43.	Gadhe	Partial
44.	Karabeli	Partial
45.	Karambeli Tarf Taloje	Partial
46.	Khairwadi	Partial
47.	Kondale	Partial
48.	Kondap	Partial
49.	Luniwali	Partial
50.	Machiprabal	Full
51.	Mahodar	Partial
52.	Maldunge	Partial
53.	Mohope	Partial
54.	Morbe	Partial
55.	Nere	Partial
56.	Nitale	Partial
57.	Pali Bk.	Partial
58.	Poyanje	Partial
59.	Ritghar	Partial

S No.	VILLAGE	STATUS
60.	Sangatoli	Partial
61.	Shriavali	Partial
62.	Tamsal	Partial
63.	Usarli Bk.	Partial
64.	Vavanje	Partial
65.	Vihighar	Partial
66.	Wajapur	Full
67.	Waje	Partial
68.	Wangani Tarf Taloje	Partial
69.	Wangani Tarf Waje	Partial
70.	Wardoli	Partial

DISTRICT : THANE**TEHSIL : ULHASNAGAR**

S No.	VILLAGE	STATUS
71.	Ambhe	Partial
72.	Bandhanwadi	Partial
73.	Bendshil	Partial
74.	Bhoj	Partial
75.	Bohonoli	Partial
76.	Chikhaloli	Partial
77.	Chinchvali	Partial
78.	Dhavale	Partial
79.	Goregaon	Partial
80.	Jambhivali	Partial
81.	Kasgaon	Partial
82.	Katrap	Partial
83.	Kushavali	Partial
84.	Savaroli	Partial
85.	Shiravali	Partial
86.	Shirgaon	Partial
87.	Vangani	Partial
88.	Varade	Partial
89.	Wadi	Partial

Annexure-C

(see section 2)

MODIFICATION TO THE BOUNDARY OF THE ESZ - EXCEPTIONS AND EXEMPTIONS IN THE 200 M. BUFFER ZONE

Reference Number corresponding with the map 1 and 2	Areas or villages for which exemptions are sought	Landuse	Remarks
Thane District			
1	Jambivali, (Ambernath)	Urbanisable Zone 1	The U-1 zone of Ambernath Municipal Council abuts the F Zone the buffer zone is less than 200 M. or no buffer is proposed
2.	Jambhaval, (Ambernath) Katrap, (Badlapur)	Industrial Zone and Urbanisable Zone I	The I-Zone of Ambernath Additional Industrial Estate planned by Maharashtra Industrial Development Corporation and U-I Zone of Kulgaon Badlapur Municipal Council abuts the F-Zone the buffer zone is less than 200 M. or no buffer is proposed
Raigad District			
3.	Goregaon, Vangani	Urbanisable Zone 2	U-2 Zone of the sanctioned Regional Plan abutting the F Zone.
4.	Vangani	Urbanisable Zone 1	U-1 Zone of the dormitory town planned in the 1973 sanctioned Regional Plan abutting Forest Zone
5.	Neral	Urbanisable Zone 1	U-1 Zone of 1999 sanctioned Regional Plan abutting F Zone
6.	Pali Tarf Verde, Umroli, Asane, Kasane, Vanjale, Kariwali, Paliwali, Bhisegaon	Urbanisable Zone 2	U-2 Zone of the sanctioned Regional Plan abutting the F Zone.
7.	Boregaon Bk., Warose Tarf Wankhal, Naniwal	Morbe Dam	Earthen dam is under construction for drinking water supply benefiting Navi Mumbai and other adjoining towns. Excavation of dam floor and strengthening of embankment by using local material and for repairs and maintenance may be necessary.
8.	Chowk Maniwali, Nadhal, Lodhivali	Railway Line	The buffer Zone is restricted upto the railway line which acts as a physical buffer for development.
9.	Barwai, Pali Bk.	Road and Railway Line	The buffer Zone is restricted upto the railway line which acts as a physical buffer for development.
10.	Bhingarwada, Bherle	Railway Line	The buffer Zone is restricted upto the railway line which acts as a physical buffer for development.
11.	Nere, Sangartoli	River Gadhe	River acts as the natural buffer, no additional buffer is therefore proposed.
12.	Gadhe	River Gadhe	River acts as the natural buffer, no additional buffer is therefore proposed.
13.	Khairwadi	River Lendhe	River acts as the natural buffer, no additional buffer is therefore proposed.
14.	Mohodar	River Nande	River acts as the natural buffer, no additional buffer is therefore proposed.

Annexure-D

[see section 4(a)(iv)(3)]

PERMISSIBLE DEVELOPMENTAL ACTIVITIES IN MATHERAN ECO-SENSITIVE ZONE**1. FOREST ZONE**

- 1.1 When any land is situated outside Reserve Forest, Protected Forest, Acquired Forest or Forests as defined as per the Supreme Courts Order dated 12th December 1996, the development of such land shall be regulated in accordance with the provisions for Green Zone-2.

2. GREEN ZONE-2

- 2.1 The permissible uses in Green Zone-2 (G-2 Zone) are as follows:-

- (a) Dwelling Units for the bona fide use of the holder as per Revenue Department records of any cultivated land, held exclusively for the purpose of agricultural activities.
- (b) Horticulture, floriculture, and, agricultural and allied activities of rice and poha mill, poultry farms, cattle stables, piggeries and sheep farms.
- (c) Religious places, crematorium and cemetery.
- (d) Schools, pre-primary school and health centre.
- (e) Clinics and dispensaries.
- (f) Roads and bridges, railways, underground pipelines and cables, electricity transmission lines, communication towers, small check dams for watershed management, ropeways

- 2.2 The minimum plot size shall be 0.4 ha.

3. GREEN ZONE-1

- 3.1 The permissible uses in Green Zone-1 (G-1 Zone) are as follows:-

- (a) Dwelling Units for the bona fide use of the holder as per Revenue Department records of any cultivated land, held exclusively for the purpose of agricultural activities.
- (b) Holiday resort and holiday homes.
- (c) Educational, medical, social, cultural and religious institutions along with residential quarters and shops for the staff on plots not be less than 2.5 ha.
- (d) Schools, pre-primary school and health centre.
- (e) Clinics, dispensaries and health centres.

- (f) Storage of LPG cylinders.
- (g) Horticulture, floriculture, and, agricultural and allied activities of rice and poha mill, poultry farms, cattle stables, piggeries and sheep farms.
- (h) Religious places, crematorium and cemetery.
- (i) Parks, gardens, play fields, camping grounds with public conveniences.
- (j) Roads and bridges, railways, underground pipelines and cables, electricity transmission lines, communication towers, small check dams for watershed management

3.2 The minimum plot size shall be 0.4 ha.

4. **URBANISABLE ZONE-2**

4.1 The permissible activities in Urbanisable Zone-2 are :-

- (a) Dwelling Units for the bona fide use of the holder as per Revenue Department records of any cultivated land, held exclusively for the purpose of agricultural activities.
- (b) Non polluting scientific institutions
- (c) Schools, pre-primary school and health centre
- (d) Clinics, dispensaries and health centres
- (e) With the prior approval of the Monitoring Committee, hotels, tourists resorts, holiday homes, motels and club houses
- (f) Houses for residential purposes only
- (g) Parks, gardens, play-fields and camping grounds with public conveniences
- (h) Religious places, crematorium and cemetery.
- (i) Horticulture, floriculture, and, agricultural and allied activities of rice and poha mill, poultry farms, cattle stables, piggeries and sheep farms
- (j) Retail shops, whole sale shops, restaurants and banks
- (k) Government offices
- (l) Garages, petrol pumps, automobile repair workshops
- (m) With prior approval of the Monitoring Committee, public services and utility establishment of water treatment plant, sewage treatment plant, solid waste treatment and disposal facilities, electricity sub-station, gas works, fire brigade, police station, telephone exchange, bus shelters, terminals and depots
- (n) Roads and bridges, railways, underground pipelines and cables, electricity transmission lines, communication towers, small check dams for watershed management

4.2 The minimum plot size for item (b) to (f) of paragraph 4.1 shall be 2,000 sq. m.

5. **URBANISABLE ZONE-1**

- 5.1 In preparing the sub-Zonal Master Plan for Matheran Municipal Council area the recommendations of the report titled Matheran : A Comprehensive Heritage Listing Proposal commissioned by the Mumbai Metropolitan Region – Heritage Conservation Society shall be taken into account.
- 5.2 The development of lands within the Urbanisable Zone-1 of Neral and Wangani falling outside the area under the Layout prepared as a part of the final Regional Plan 1973 shall be regulated in accordance with the provisions for Green Zone-1.

6. **GOATHAN and GAOTHAN EXPANSION**

- 6.1 The following provisions irrespective of Zones shall regulate Gaothan and Gaothan Expansion.
- 6.2 The boundary of the Gaothan shall be as shown in the revenue maps when the Regional Plan came into force.
- 6.3 Gaothan Expansion may be permitted by the Monitoring Committee based on needs and requirements of and for existing gaothan residents only.
- 6.4 The lands in Gaothan and Gaothan Expansion may be used for any of the following purposes :
- (a) Residential.
 - (b) Shops, garages, small eating places, banks and post offices.
 - (c) Schools.
 - (d) Community centres and other social institutions.
 - (e) Religious places.
 - (f) Clinics, dispensaries and health centres.
 - (g) Essential public services and utilities including local Government offices.
 - (h) Stables for domestic animals subject to limit of 5 animals on each plot.
 - (i) Traditional household industries.
 - (j) Storage of crop, fodder, manure, agricultural implements and other similar needs
 - (k) Parks, gardens and playgrounds.
 - (l) Public conveniences.
 - (m) Storage of fuels for domestic and commercial uses.

6.5 Floor Area Ratio and Ground Coverage

<u>Area</u>	<u>FAR</u>	<u>Ground coverage</u>
Gaothan	1.00	—
Gaothan Expansion	0.40	40%

Note : The classification of zones referred to above is as per the sanctioned Regional Plan of the Mumbai Metropolitan Region, September 1999.